



आपदा समाचार

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (UP SDMA)



VOLUME - IV

MARCH 2025



महाकुम्भ सांस्कृतिक पर्व

गतिविधियाँ और उपलब्धियाँ | (वार्षिक संस्करण)



लेपिटनेंट जनरल योगेन्द्र डिमरी

पी.वी.एस.एम., ए.वी.एस.एम., वी.एस.एम., (से.नि.)

Lt Gen Yogendra Dimri

PVSM, AVSM, VSM (Retd)

उपाध्यक्ष / Vice Chairperson

उ.प्र. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

UP State Disaster Management Authority

बी-१ ब्लॉक, प्रथम तल, पिकप भवन, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010

B-1 Block, First Floor, PICUP Bhawan, Vibhuti Khand,
Gomtinagar, Lucknow-226010

संदेश

प्रिय पाठकों,

यह अत्यंत गर्व और प्रसन्नता का विषय है कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की आपदा समाचार पत्रिका ने आप सभी के सहयोग से एक वर्ष की सफल यात्रा पूरी कर ली है। इस एक वर्ष में हमने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में किए गए उल्लेखनीय कार्यों, नवाचारों और सामूहिक प्रयासों को आप तक पहुँचाने का प्रयास किया।

इस वर्ष महाकुम्भ 2025 के आयोजन में प्रदेश सरकार के सभी विभागों ने न सिर्फ हमारी सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक आस्था को गौरवान्वित किया है, बल्कि महाकुम्भ आयोजन को आपदा प्रबंधन के लिए एक चुनौतीपूर्ण अवसर के रूप में स्वीकार कर बेहतरीन कार्य किया है।

हमारी टीम ने मॉक ड्रिल्स, जनजागरूकता अभियानों, तकनीकी सुदृढ़ीकरण और आपदा न्यूनीकरण पहलों को दस्तावेजीकरण करते हुए एक प्रेरणास्रोत पत्रिका तैयार की, जिससे न केवल प्रशासनिक ढांचे को बल्कि आमजन को भी आपदाओं के प्रति जागरूक एवं सशक्त बनाया जा सके।

भविष्य की तरफ आगे बढ़ते हुए, हमारा संकल्प है कि हम आपदा प्रबंधन में नवीनतम तकनीकों, सामुदायिक सहभागिता और बहुस्तरीय समन्वय को और अधिक मजबूत करें। हम चाहते हैं कि भविष्य में हमारी पत्रिका न केवल उपलब्धियों का दस्तावेज बने, बल्कि नवाचारों, अनुसंधान, और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने का भी एक जीवंत मंच बन जाए।

हमारा लक्ष्य है-

- * यह पत्रिका एक संवाद का माध्यम एवं एक ऐसा मंच बने, जहाँ आपदा न्यूनीकरण के अनुभवों का आदान-प्रदान हो,
- * हर नागरिक को आपदा के प्रति जागरूक और सक्षम बनाना,
- * हर गाँव और हर शहर को आपदा-प्रतिरोधी बनाना,
- * उत्तर प्रदेश को आपदा प्रबंधन में राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक उदाहरण के रूप में स्थापित करना।

इस यात्रा में आप सभी का निरंतर सहयोग और सक्रिय भागीदारी ही हम सबके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। आइए, हम मिलकर न केवल वर्तमान को सुरक्षित बनाएं, बल्कि भविष्य को भी आश्वस्त करें।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित,
उपाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

संपादकीय

एक वर्ष की यात्रा : प्रतिबद्धता, उपलब्धियाँ और भविष्य

प्रिय पाठकों,

हमें अत्यंत हर्ष है कि हमारी पत्रिका ने सफलतापूर्वक एक वर्ष पूर्ण कर लिया है। इस यात्रा में आप सभी पाठकों, लेखकों, अधिकारियों और विशेषज्ञों का अपार सहयोग एवं विश्वास हमारी सबसे बड़ी ताकत रहा।

वर्ष 2024, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के लिए उपलब्धियों और नवाचारों का वर्ष रहा। इस वर्ष राज्य ने संचार व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने, सामूहिक मॉक ड्रिल्स आयोजित करने, तकनीकी समाधानों को अपनाने और जन जागरूकता अभियानों को समय से अंतिम पायदान तक पहुंचाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। मुख्य कार्यक्रमों में मथुरा में भूकंप एवं अग्नि मॉक ड्रिल, औरैया में ऑफ साइट आपातकालीन अभ्यास, नरौरा परमाणु संयंत्र में बाह्य-स्थल आपात अभ्यास, तथा बागपत, बिजनौर, हापुड़ और मीरजापुर में विभिन्न नवाचार और जनजागरूकता पहलें प्रमुख रहीं।

इस पत्रिका का पहला वर्ष हमारी आकांक्षाओं की नींव है। आने वाले वर्षों में हमारा लक्ष्य है कि हम इस मंच को और अधिक समृद्ध बनाएं, जहाँ वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएँ, स्थानीय अनुभव, नवीनतम तकनीकी उपाय, नीति संवाद और शोध आधारित लेख समाहित हों। हम इसे आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में न केवल एक सूचना-पत्र, बल्कि दिशा-प्रदर्शक एवं प्रेरणास्रोत दस्तावेज बनाना चाहते हैं।

हम आपके सुझावों, विचारों और सक्रिय सहभागिता का स्वागत करते हैं। आइए, मिलकर एक सुरक्षित, सशक्त और आपदा-रोधी उत्तर प्रदेश के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएँ।

सादर,

(डॉ. कनीज़ फतिमा)

परियोजना निदेशक (सूखा) उत्तर प्रदेश राज्य आपदा

प्रबंधन प्राधिकरण

Editor

Dr. Kaneez Fatima
Project Director (Drought), UP SDMA

Technical Support

Mr. Prashant Kumar
Project Associate, UP SDMA

Need for Disaster Management Exercises

Brig. Ajay Gangwar (Rtd.)

Hazards like earthquakes, floods, fire and industrial accidents often manifest as disasters suddenly and unpredictably with serious consequences. Such disasters result in widespread loss of life, property and infrastructure. Timely and effective response during disasters can mean the difference between life and death. Such a coordinated response will save lives and minimise injuries. Disaster Management Exercise (DMEx) is an essential tool to ensure that communities, emergency responders, organizations and individuals are prepared to deal with emergencies efficiently and effectively.

Disaster Management Exercises DMExs may be discussion based like Tabletop Exercises or action based like Mock Exercises. In such exercises, imaginary but real life like emergency situations are presented to the participants who are expected to take decisions or actions based on the information given to them within the framework of existing plans, procedures, resources and capabilities.

DMExs are a rehearsal of actual response to possible disasters and are conducted during the Preparedness Phase of DM Cycle. The scope of DMEx depends on the preparation and training needs. It may include one or more of the objectives enumerated in succeeding paragraphs.

Practising, Testing and Refining Disaster Management Plans DMExs are an effective way to test the viability of DM Plans. Actual response during emergency situations is carried out in high stress conditions with constraints of both time and resources. It is thus essential that the response is practiced repeatedly during normal times to evaluate preparedness and capabilities.

DMEx simulate real-life pressures, such as time constraints, equipment shortages, and communication failures. Hence, it may be discovered that communication systems are inadequate or that evacuation plans need improvement. By identifying these gaps, plans and standard operation procedures (SOPs) can be refined. Testing the readiness of critical infrastructure, such as hospitals and other emergency support functions is also a key element of DMExs.

Enhancing Preparedness and Response Capabilities

One of the primary reasons for conducting DMEx is to enhance preparedness. These exercises provide a realistic simulation of disaster scenarios, enabling emergency responders, organizations, and the public to practice their responses in a controlled environment. This preparation is crucial because, during actual disasters, the speed and efficiency of the response can significantly reduce casualties and damage. The gaps observed in preparedness and capabilities can be addressed by training, additional resources and coordination.

Strengthening Coordination Among Stakeholders Disasters require a coordinated response from multiple agencies and organizations, including local, state, and national government bodies, non-governmental organizations (NGOs), and private entities. Disaster Management Exercises foster collaboration among these various stakeholders, ensuring that everyone knows their roles and responsibilities.

This collaboration ensures that each agency is familiar with the other's operations and can coordinate effectively in a real crisis. Exercises provide clarity in command and control protocols. They streamline decision-making in a multiple stakeholder environment. Improving Public Awareness and Education Public involvement in Disaster Management exercises is just as important as the participation of emergency responders. Community members play a vital role in disaster preparedness, and mock drills can help educate the public on what to do in the event of an emergency. By familiarizing individuals with evacuation routes, emergency shelters, and basic survival techniques, these exercises reduce panic and confusion during real-life situations.

Building Confidence and Reducing Anxiety

Disaster Management Exercises play a psychological role in reducing anxiety and building confidence. Individuals and communities who have practiced their response to potential disasters feel more empowered and less fearful of the unknown. This mental preparedness can lead to better decision-making in high-pressure situations, contributing to more effective outcomes during actual disasters.

Periodicity

The DMEs may be conducted as needed but the periodicity may not be less than once a year. For recurring or frequent hazards, DMEx should be scheduled before the onset of the season. For other hazards, DMEx should be conducted annually.

In conclusion, DMEs are indispensable for improving disaster preparedness at every level—governmental, organizational, and individual. These exercises ensure that emergency responders and the public are well-equipped to handle emergencies, foster coordination among multiple agencies, and help refine existing disaster response plans. The importance of these exercises cannot be overstated, as they save lives and reduce the overall impact of disasters when they inevitably occur.



Akbar Fort, Prayagraj MEx.

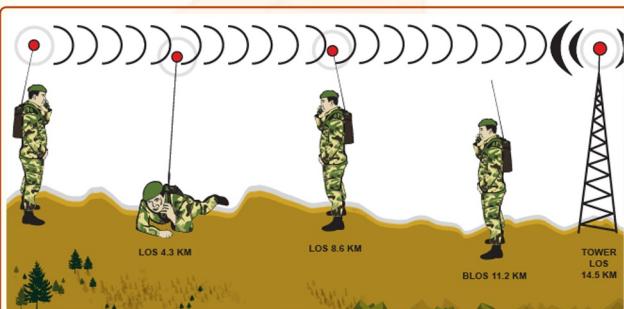
उत्तर प्रदेश में पुलिस संचार प्रणाली : आपदा प्रबंधन की रीढ़

श्री सुनील कुमार सिंह, (आई०पी०एस०)
महानिरीक्षक/निदेशक (पुलिस दूरसंचार) उ०प्र०, लखनऊ



उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और जनसंख्या बहुल राज्य में आपातकालीन परिस्थितियों, विशेषकर दैवीय आपदाओं के समय, प्रभावी संचार प्रणाली की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। राज्य की पुलिस संचार व्यवस्था को इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बहुआयामी, तकनीकी रूप से सशक्त और 24/7 सक्रिय रूप में विकसित किया गया है।

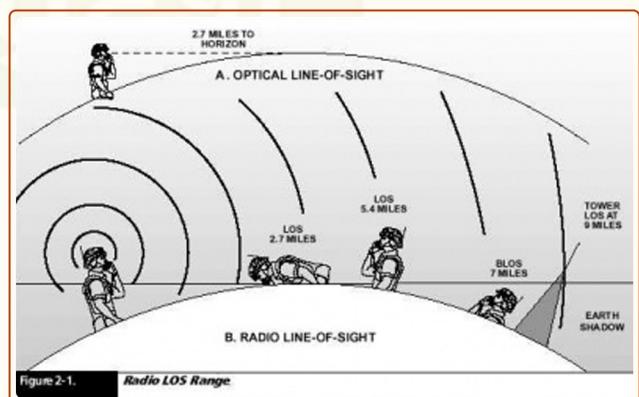
सुदृढ़ संचार नेटवर्क की आधारशिला



प्रदेश में लंबी दूरी की संचार आवश्यकताओं के लिए एचएफ (हाई फ्रीक्वेंसी) संचार प्रणाली स्थापित की गई है, जो मोर्स कोड और आरटी तकनीक पर आधारित है। इसके साथ ही, पुलिस रेडियो मेल (लाइन कम्युनिकेशन) और पोलनेट (POL-NET) जैसी उपग्रह आधारित संचार प्रणालियाँ भी कार्यरत हैं। ये सभी संचार व्यवस्थाएँ प्रदेश के प्रत्येक जनपद में 24 घंटे, सप्ताह के सातों दिन कार्यशील

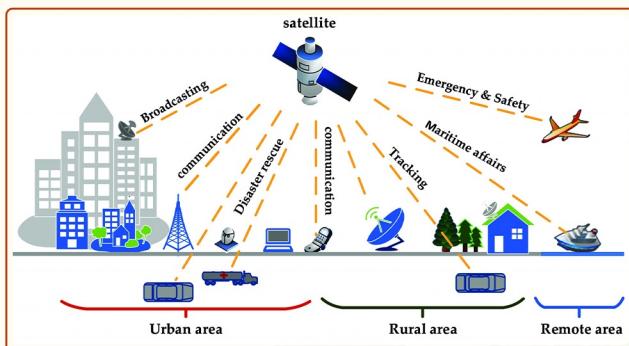
स्थानीय स्तर पर प्रभावी संचार व्यवस्था

जनपद स्तर पर स्थानीय संचार प्रणाली के रूप में पुलिस कंट्रोल रूम (जनपद नियंत्रण कक्ष, नगर नियंत्रण कक्ष, यातायात नियंत्रण कक्ष आदि) की स्थापना की गई है। इन केंद्रों को वीएचएफ (VHF) आरटी संचार प्रणाली के माध्यम से पुलिस थानों, चौकियों और वरिष्ठ अधिकारियों से जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त, लैंडलाइन और CUG मोबाइल फोन की भी व्यवस्था है, जिससे तत्काल सूचना का आदान-प्रदान संभव हो पाता है।



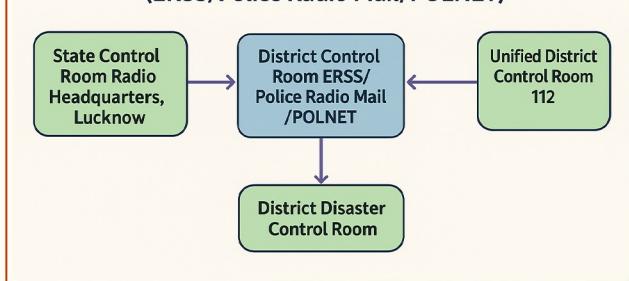
आपदा के समय संचार प्रणाली की भूमिका

किसी भी प्रकार की आपदा जैसे भूकंप, बाढ़, आंधी-तूफान, आग लगना या ट्रेन दुर्घटना के दौरान, संचार प्रणाली की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से संबंधित विभागों अग्निशमन, स्वास्थ्य, नगर निगम, विद्युत, परिवहन, खाद्य एवं रसद, जल निगम, भू एवं राजस्व, सेना और नागरिक सुरक्षा आदि को त्वरित सूचना भेजी जाती है।



विशेष उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार के आदेशानुसार, हर वर्ष 1 जून से 31 अक्टूबर तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 113 चयनित स्थलों पर वायरलेस सेट स्थापित कर दिए जाते हैं। यदि अन्य किसी जनपद में भी बाढ़ जैसी आपदा की आशंका होती है, तो वहाँ भी वायरलेस सेट स्थापित कर तदनुसार रेडियो कमिंयों की ड्यूटी लगाई जाती है।

**Uttar Pradesh Communication Grid
(ERSS/Police Radio Mail/POLNET)**



मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure & SOP)

आपदा प्रबंधन के दौरान पुलिस दूरसंचार विभाग द्वारा निम्न लिखित SOP अपनाई जाती है:

- आपदा नियंत्रण कक्ष की स्थापना:** आपदा स्थल के समीप सुरक्षित स्थान पर तत्काल एक अस्थाई कंट्रोल रूम स्थापित किया जाता है, जो जनपद नियंत्रण कक्ष की आवृत्ति पर संचालित होता है।
- संचालन का नियंत्रण:** आपदा स्थल जिस नियंत्रण कक्ष के क्षेत्राधिकार में आता है (नगर या जनपद), संचार उसी चैनल पर संचालित किया जाता है।

- सहायक रेडियो अधिकारी की भूमिका:** प्रत्येक परिक्षेत्रीय मुख्यालय में नियुक्त सहायक रेडियो अधिकारी संबंधित जनपदों में पहुंचकर संचार व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं।
- संचार उपकरणों की पूर्ति:** आवश्यक वायरलेस सेट जनपद रिजर्व या परिक्षेत्रीय रिजर्व से उपलब्ध कराए जाते हैं।
- मुख्यालय से सहायता:** यदि अतिरिक्त उपकरणों की आवश्यकता हो, तो तत्काल रेडियो मुख्यालय को मांग-पत्र भेजा जाता है, जिससे उपकरण मंगाकर समय से

आवश्यकता हो, तो तत्काल रेडियो मुख्यालय को मांग-पत्र भेजा जाता है, जिससे उपकरण मंगाकर समय से अधिष्ठापित किए जाते हैं।

नागरिक सहभागिता और जनजागरूकता

प्रदेश के सभी जनपदों में सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस कंट्रोल रूम और संबंधित अधिकारियों के टेलीफोन नंबरों की होडिंग्स लगाई जाती हैं, ताकि नागरिक किसी भी आपदा की जानकारी होने पर त्वरित रूप से पुलिस को सूचित कर सकें।

निष्कर्ष - उत्तर प्रदेश की पुलिस संचार व्यवस्था आधुनिक तकनीकों, प्रशिक्षित रेडियो स्टाफ और सुसंगठित नेटवर्क के माध्यम से न केवल आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाती है, बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा और त्वरित राहत कार्यों के लिए भी एक मजबूत आधार प्रदान करती है।



इन्टरस्टेट डिस्ट्रिक्ट वी०एच०एफ० "आपदा नियंत्रण कक्ष" संचार प्रिंट मैप

UP SDMA Volunteers Training

**Shri Praveen Kishor,
Project Coordinator (Training)**

Introduction

Disasters, whether natural or man-made, are indiscriminate forces that strike without warning, leaving behind a trail of destruction. They do not differentiate between nations or communities, rich or poor, young or old. Their impact is universal, causing significant loss of life, property, and livelihoods. When disasters occur, it is the communities that are the first to respond, acting instinctively and selflessly, irrespective of their profession, social standing, caste, or cultural identity.

The MahaKumbh 2025 celebration is a unique event, occurring once in 144 years' life span of present generation, and is expected to be witnessed by over 40 - 45 Cr pilgrims with more than 15 to 20 Lakh residential pilgrims, from all over India and other countries. This brings unique challenges in mass gathering event management, in day-to-day functioning and during emergencies. The role of trained community volunteers having technical expertise in emergency response and willingness to be a part of management framework is not only essential but a necessity and provides essential link between administration and pilgrims.

Target Group

Affiliated and Spontaneous volunteers to include:

- a) Affiliated Volunteers- Civil Defence (CD), Home Guards (HG) and Aapda Mitra.
- b) Spontaneous Volunteers- National Cadet Corps (NCC), Nehru Yuva Kendra

Training Objective

The following objectives were determined to be achieved during one-day training schedule:

- a) To familiarise all trainees with general layout of Mela Kshetra to include sector layout / internal roads / pontoon bridges / Ghats, critical infrastructures and facilities planned inside Mela Kshetra.
- b) Their roles in assisting pilgrims include location finding, assisting pilgrims to solve their concerns, directing them on desired route and escorting missing persons to lost and found centres.
- c) To assist Law and Order agencies in crowd control as per their directions.
- d) Be able to act as first responder in case of any emergency in terms of skill development, pertaining to use of fire extinguishers, fire evacuation, ghat safety, boat safety, carriage of casualty, first aid, and CPR.
- e) Developing effective communication skill while interacting with pilgrims.

Scope

UP SDMA nominated about 6000 volunteers both affiliated and spontaneous volunteers for the training. Twenty-Two one day trainings were conducted with about 250 to 500 participants in each training.

The scope of the training program is to sensitize the volunteer force on infrastructure layout, traffic plan, operational plans, facilities and important utilities provided in MahaKumbh Mela. This will make the volunteers familiar with Mela layout and could effectively assist pilgrims by guidance and necessary support.

The training program is focused on a Sugam and Surakshit MahaKumbh through a group of trained volunteers by preparing them for tasks such as helping at the lost & found Centres, managing help desks, assisting differently-abled individuals and supporting senior citizens.

The volunteers were trained to respond to a variety of situations, including emergency scenarios. The training included modules on rescue operations, first aid, firefighting, equipping volunteers with the essential skills required for emergency response.

The program also catered attitude building, encouraging volunteers to adopt a proactive and compassionate approach to relief and rehabilitation activities.

Familiarisation of Mela Kshetra: Volunteers are given know-how with the map layout of the Mela Kshetra. This helps in crowd management and guiding the pilgrims.

Demonstrations & Hands on Training: Extensive training and Simulations on First-Aid, Stampede, Flood, Fire, Drowning, Search & Rescue etc. to the Civil Defence (CD), Home Guards (HG), National Cadet Corps (NCC), Nehru Yuva Kendra Sangathan (NYKS), and Aapda Mitra, BS & G, NSS.

Support for Vulnerable Group: Special training is provided to assist differently abled individuals, senior citizens, and children, ensuring inclusive support services during the event. Soft skill training has been imparted to take care of the pilgrims empathetically. **Swatch and Sugam Kumbh:** Volunteers were apprised about hygiene and sanitation facilities in the mela Kshetra and the responsible agencies for its maintenance/ restoration and necessary briefing was given regarding their role for its implementation.

Training Goal

The volunteer training goal is aligned with the state goal, of providing a pleasant experience of Mahakumbh 2025, to all pilgrims, by ensuring their safety and security as well as providing them all essential administrative help/support during their stay in Mela Kshetra.

Necessity for Volunteer Development

- * To enhance Disaster Preparedness
- * To strengthen Community Resilience
- * To improve the area familiarization
- * To facilitate sustainable and safe crowd management

The training programs and simulations/mock drills are designed to train the volunteers to make quick decisions and carry out effective and efficient response in critical situations with empathy. The on-ground training will boost confidence on in the actual execution during emergencies in any real-life incidents. Soft skills training is also a part of the training program to improve and take command over communication skills. Team coordination, flawless communication and response to disasters is a part of the extensive training program.

By investing in a well-structured volunteer training program, the MahaKumbh 2025 aims to establish a secure and efficiently managed environment, ensuring a seamless and safe experience for all attendees.



Home Guards Training

महाकुंभ मेला : गीता प्रेस शिविर में भीषण अग्निकांड, फायर ब्रिगेड ने 30 मिनट में आग पर पाया काबू

श्री अमन शर्मा (उपनिदेशक अग्निशमन), श्री प्रमोद शर्मा (मुख्य अग्निशमन अधिकारी)
उ० प्र० अग्निशमन तथा आपात सेवा महाकुम्भ मेला, प्रयागराज

महाकुम्भ मेला के दौरान दिनांक 19 जनवरी 2025 को 16:03 बजे पीपा पुल नं 13 पर लगी पुलिस पिकेट द्वारा आईसीसीसी कंट्रोल रूम को आग लगने की सूचना मिली। फायर स्टेशन खाक चौक व अखाड़ा से फायर यूनिट रवाना की गई। परम पूज्य स्वामी वासुदेवानन्द सरस्वती जी महाराज शिविर में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों ने भी धुआं देखकर तत्काल टर्नआउट कराया। लगभग 07 फायर टेंडर 16:05 बजे घटनास्थल पहुंचे। आग गीता प्रेस शिविर, मोरी मार्ग सेक्टर 19 में फूस के पंडालों में लगी थी। आग की भयावहता को देखते हुए उच्चाधिकारियों को सूचित कर अन्य फायर टेंडर बुलाए गए। इस दौरान 03 एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट हुए। तेज हवा से आग के फैलने की संभावना बनी थी, जिसे वाटर कर्टन व मॉनिटर ब्रांच से नियन्त्रित किया गया। आग के पास से रेलवे पुल से ट्रेन गुजरने के कारण ट्रेनों को अलग-अलग स्टेशनों पर रोका गया। 45 फायर टेंडरों की मदद से 30 मिनट में आग पर पूरी तरह काबू पालिया गया।



वरिष्ठ अधिकारी श्री भानु भास्कर (अपर पुलिस महानिदेशक), श्री राजेश द्विवेदी (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक), श्री अमन शर्मा (उपनिदेशक अग्निशमन), श्री प्रमोद शर्मा (मुख्य अग्निशमन अधिकारी) आदि अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। अग्निशमन टीमों ने 25-30 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। इस अग्निदुर्घटना में 100 झोपड़ियां जलकर नष्ट हो गयी तथा 200-300 अस्थायी पंडाल बचाए भी गये। प्रभावितों को राहत शिविरों में भेजा गया तथा स्थानीय पुलिस ने क्षेत्र को सुरक्षित किया, और चिकित्सा दल ने तत्काल एंबुलेंस व चिकित्सक घटना स्थल पर भेजे। विभागों के आपसी सहयोग एवं सामंजस्य से इस घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई।

नोट- उ० प्र० अग्निशमन तथा आपात सेवाएं विभाग के द्वारा महाकुंभ 2025 के दौरान आग से सुरक्षा और आपातकालीन स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक अग्निशमन तकनीकों जैसे-फायरफाइटिंग ऑल टेरेन व्हीकल (ATV), फायरफाइटिंग बोट, वॉटर कर्टन होज़, फायर ट्रेस ट्यूब टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया गया। इन अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से प्रशासन ने महाकुंभ 2025 को सुरक्षित और सफल बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम उठाया है।

Enhancing Disaster Preparedness in District through Mock Exercise

Earthquake and Fire Disaster Drill (Mathura)

Sh. Shailendra Kumar Singh (IAS) D.M., Mathura
Sh. Yoganand Pandey (PCS) A.D.M. (F/R), Mathura
Sh. Sushil Kumar (District Disaster Expert), Mathura

Located within Earthquake Zones III and IV, Mathura district is subject to moderate to high seismic vulnerability a risk compounded by the presence of industrial establishments, high-rise structures, and a significant influx of tourists. In a proactive move to assess and enhance disaster preparedness, a comprehensive mock drill was conducted on September 20, 2024, under the aegis of the UP SDMA.



Evacuation

The exercise was executed across four strategically selected sites, simulating both earthquake and fire emergency scenarios. It brought together a coordinated response from multiple agencies, including the Police, Fire & Emergency Services, Civil Defence, and observers from the NDRF, SDRF and the Indian Army. Preceding the drill, participants engaged in a detailed orientation session and a table-top exercise to ensure operational readiness. The primary objectives of the drill were to evaluate the efficiency of emergency response mechanisms, assess the vulnerability of critical infrastructure, and reinforce interagency coordination among Emergency Support Functionaries. The entire operation was closely monitored in real time from the Emergency Operations Centre, enabling a robust analysis of response capabilities and procedural efficacy.

Fire Drill at Bajaj Hindusthan Sugar Limited (Saharanpur)

Sh. Manish Bansal (IAS) D.M., Saharanpur
Sh. Rajnish Kumar Mishra (PCS) A.D.M. (F/R),
Saharanpur



Sh. Pankaj Kumar Mishra (District Disaster Expert), Saharanpur On September 20, 2024, a mock drill was conducted at M/s Bajaj Hindusthan Sugar Ltd. Distillery Unit, Saharanpur, simulating a fire incident triggered by static charge during ethanol loading. The scenario unfolded at 12:15 PM, prompting an immediate and coordinated response from the site's security, fire, EHS, and medical teams. One injured individual was promptly rescued and transported to a medical facility. The fire was brought under control by 12:39 PM, with an 'All Clear' declared at 12:45 PM. The drill effectively engaged all emergency functionaries, testing the efficiency of communication, coordination, and operational response. It also reinforced critical aspects of emergency preparedness, including evacuation procedures, equipment handling, and command structure implementation.

मॉकड्रिल्स

औरैया ऑफ साइट मॉकड्रिल: खानपुर गाँव, में अग्नि व रिसाव से निपटने की तत्परता

डॉ० इंद्रमणि त्रिपाठी (आई०ए०एस०), जिलाधिकारी
श्री महेंद्र पाल सिंह, अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
श्री दीपक कुमार, आपदा विशेषज्ञ



गेल इंडिया लिमिटेड मॉकड्रिल

25 सितंबर 2024 को दोपहर 1 बजे, औरैया जनपद के खानपुर गाँव में गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा गैस रिसाव और आग से निपटने के लिए ऑफ-साइट मॉकड्रिल आयोजित की गई। मॉकड्रिल में टैंकर की टक्कर से एम.एफ.ओ. और एल.पी.जी. टैंकर में रिसाव हुआ, जिससे आग लग गई। घटना के बाद, गेल पाता और एन.टी.पी.सी. की दमकल गाड़ियाँ घटनास्थल पर पहुंची। आग बुझाने और रिसाव रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए गए। सभी धायलों को अस्पताल भेजा गया। मॉकड्रिल में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, एसडीआरएफ और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। प्रतिक्रिया प्रणाली, समन्वय और त्वरित कार्रवाई को संतोषजनक पाया गया।

बुलन्दशहर नरौरा परमाणु विद्युत केन्द्र में बाह्य-स्थल आपात अभ्यास: एक महत्वपूर्ण कदम

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह (आई०ए०एस०), जिलाधिकारी
श्री अभिषेक कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
श्री मोहित, आपदा विशेषज्ञ



जिला प्रशासन एवं स्थानीय नागरिकों के मध्य समन्वय बैठक

21 सितंबर 2024 को नरौरा परमाणु विद्युत केन्द्र, बुलन्दशहर में बाह्य-स्थल आपातकालीन मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य परमाणु आपात स्थितियों में त्वरित व समन्वित प्रतिक्रिया का परीक्षण था। अभ्यास में आपातकालीन वर्गीकरण, विकिरण निगरानी, चेतावनी प्रसार, मेडिकल सहायता, निकासी और विकिरण रोधी दवाओं के वितरण जैसी गतिविधियाँ शामिल थीं। जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, चिकित्सा, अग्निशमन, पुलिस व अन्य विभागों ने सक्रिय भागीदारी की। अभ्यास ने दर्शाया कि समन्वयित प्रयासों से किसी भी परमाणु आपात स्थिति का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सकता है। समापन समीक्षा में अभ्यास को सफल बताया गया।

बागपत औद्योगिक क्षेत्र में मॉकड्रिल



जनपद बागपत के औद्योगिक क्षेत्र में आगजनी की बढ़ती संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जो औद्योगिक दुर्घटनाओं से निपटने की तैयारियों का आकलन करती है। बागपत, एनसीआर का एक उभरता हुआ प्रमुख औद्योगिक केंद्र बन रहा है, जिससे इस क्षेत्र में औद्योगिक आपदाओं की संवेदनशीलता में बढ़िया हुई है।

मुख्य सीखों में शामिल हैं-शीघ्र और सुरक्षित निकासी प्रक्रिया, अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता, अग्निशमन उपकरणों का कुशल उपयोग, एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, समय प्रबंधन और प्राथमिक उपचार। इस प्रकार की मॉक ड्रिल्स वास्तविक आपदाओं की स्थिति में बेहतर तैयारी सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होती हैं।

श्री जितेंद्र प्रताप सिंह (आई०ए०एस०), जिलाधिकारी
श्री पंकज वर्मा, अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
श्री अश्वनी कुमार, आपदा विशेषज्ञ

इसी क्रम में, 13 मई 2024 को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA), बागपत एवं NDRF की 8वीं बटालियन के संयुक्त तत्वावधान में ग्रीन एनर्जी प्रा. लि. (थिंक गैस), सी०जी०एस० बली बागपत में एक मॉकड्रिल आयोजित की गई। यह अभ्यास गैस एवं ओडोरेंट रिसाव से उत्पन्न आग की परिकल्पित स्थिति पर आधारित था। मॉकड्रिल का उद्देश्य आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं, संसाधन उपलब्धता, संचार प्रणाली तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय का परीक्षण करना था।

ड्रिल के दौरान एक पाइपलाइन में रिसाव से आग लग गई, जिससे एक कर्मचारी धायल हो गया। घटना की गंभीरता के अनुसार लेवल-1 से लेवल-3 तक आपात स्थिति घोषित की गई। मौके पर फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, IOCL और NDRF की टीमें समय पर पहुंचीं और स्थिति को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया।

Case Study : बिजनौर जिले में मानव-गुलदार संघर्ष प्रबंधन

श्री अंकित कुमार अग्रवाल (आई०ए०एस०), जिलाधिकारी

श्री अरविंद कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)

श्री प्रशांत श्रीवास्तव, आपदा विशेषज्ञ

परिचय

बिजनौर, उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख ज़िला है जो उत्तराखण्ड के कार्बेट टाइगर रिजर्व और अमानगढ़ टाइगर रिजर्व के समीप स्थित है। यहाँ के वन्यजीवों में गुलदार (लेपर्ड) प्रमुख हैं, जिनकी संख्या और गतिविधि मानव बस्तियों और कृषि क्षेत्रों के साथ बढ़ते संघर्ष का कारण बन रही है। गुलदारों द्वारा मवेशियों और मानवों पर हमले की घटनाएँ प्रायः होती रही हैं, जिससे स्थानीय समुदाय में डर और चिंता का माहौल बना दुआ है।

मानव-गुलदार संघर्ष के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

- गुलदारों की बढ़ती संख्या:** बिजनौर और इसके आस-पास के वन्यजीव अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व गुलदारों का घर हैं, जिसके कारण उनकी संख्या बढ़ी है।
- कृषि क्षेत्र और फसलें:** गत्रों की खेती, जो गुलदारों और अन्य वन्यजीवों के लिए प्राकृतवास प्रदान करती है, कोलोनियों और गांवों के पास स्थित है।
- मानव आबादी के करीब वन क्षेत्र:** ज़ंगल के पास स्थित मानव बस्तियाँ और खेत गुलदारों को आकर्षित करते हैं, विशेष रूप से रात के समय।
- ग्रामीणों का व्यवहार:** शौच के लिए खेतों का रुख करना और रात को गांवों में अंधेरे में बाहर निकलना संघर्ष के मुख्य कारणों में से एक है।

मानव-गुलदार संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। ये उपाय ज़ंगल और मानव बस्तियों के बीच संघर्ष को कम करने में सहायक रहे हैं।

1. तात्कालिक कार्यवाही:

गुलदारों का रेस्क्यू और स्थानांतरण: जनवरी 2024 से अब तक 14 गुलदारों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया।

पिंजरे और कैमरा ट्रैप: गुलदारों की गतिविधि पर नजर रखने के लिए पिंजरे लगाए गए और कैमरा ट्रैप का इस्तेमाल किया गया। संवेदनशील गांवों में जागरूकता अभियान: ग्राम प्रधानों और ग्रामीणों के साथ मिलकर जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए ताकि लोग गुलदारों से बचाव के उपायों के बारे में जान सकें।

2. निरंतर समाधान:

गुलदार सुरक्षा एक्सप्रेस: यह एक यात्रा अभियान है, जिसमें विभिन्न रेंजों में गुलदारों से बचाव के उपायों की जानकारी दी जाती है। त्वरित दल (RRT): किसी भी संकट की स्थिति में विशेष कार्यवाही दल मौके पर पहुंचकर सहायता प्रदान करते हैं। शोध और विशेषज्ञों की मदद: WWF और WII के विशेषज्ञों की सेवाएँ ली गई ताकि गुलदार के व्यवहार और संघर्ष के कारणों का गहन अध्ययन किया जा सके।

3. दीर्घकालिक रणनीतियाँ:

सोलर फैसिंग और चेनलिंक फैसिंग: वन क्षेत्रों के किनारे सोलर और चेनलिंक फैसिंग लगाने की योजना बनाई गई है ताकि

गुलदार रेस्क्यू सेंटर:

गुलदारों और अन्य वन्यजीवों के लिए एक स्थायी रेस्क्यू सेंटर स्थापित करने की योजना है।

वैज्ञानिक अध्ययन: भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा गुलदारों के प्रभावित क्षेत्रों पर वैज्ञानिक अध्ययन किए जा रहे हैं, ताकि दीर्घकालीन समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

सियासत

क्यूआर कोड बना देख



क्यूआर कोड के माध्यम से जनजागरूकता

परिणाम और प्रभाव

अब तक किए गए उपायों ने सकारात्मक परिणाम दिए हैं:

गुलदारों के हमलों में कमी: रेस्क्यू ऑपरेशंस और निगरानी उपायों के कारण गुलदारों के हमलों में कमी आई है।

जागरूकता में वृद्धि: गांवों में गुलदारों से बचाव के उपायों पर अधिक जागरूकता पाई गई है।

समुदाय की सक्रिय भागीदारी: ग्रामीणों ने मिलकर जागरूकता अभियानों में सक्रिय भाग लिया और संघर्ष से बचने के उपायों का पालन किया।

भविष्य की दिशा

मानव-गुलदार संघर्ष को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए आने वाले वर्षों में निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे:

स्थायी विशेषज्ञ टीम: WWF और WII की एक स्थायी टीम गुलदारों के अध्ययन और संघर्ष को नियंत्रित करने में सहायता करेगी।

इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास: सोलर और चेनलिंक फैसिंग का कार्य तेजी से शुरू किया गया जाएगा, साथ ही रेस्क्यू सेंटर और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी सुदृढ़ किया जाएगा।

निष्कर्ष: बिजनौर जिले में मानव-गुलदार संघर्ष एक जटिल समस्या है, जिसे कई कारकों से बढ़ावा मिलता है। हालांकि, वन विभाग और स्थानीय समुदाय के बीच सहयोग, जागरूकता अभियानों और विशेषज्ञों की मदद से संघर्ष को कम किया जा रहा है। इन उपायों से यह साबित होता है कि यदि समन्वित प्रयास किए जाएं, तो मानव-वन्यजीव संघर्ष को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। यह केस स्टडी अन्य क्षेत्रों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करती है, जहाँ मानव-वन्यजीव संघर्ष की समस्या है।

Case Study

ब्रजघाट गंगा नदी, हापुड़ में फ्लोटिंग बैरिकेट्स और फ्लोटिंग जेट्टी : सुरक्षा और स्वच्छता की दिशा में एक कदम

श्रीमती प्रेरणा शर्मा (आई०ए०एस०), जिलाधिकारी

श्री संदीप कमार, अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)

श्री गजेन्द्र सिंह, आपदा विशेषज्ञ

गंगा नदी, जो भारतीय संस्कृति और धर्म का अभिन्न हिस्सा है, न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के रूप में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में स्थित ब्रजघाट, गंगा नदी के किनारे एक महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटक स्थल है। यह क्षेत्र श्रद्धालुओं द्वारा नियमित रूप से पूजा, स्नान और अन्य धार्मिक क्रियाओं के लिए प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। हालांकि, गंगा नदी में भारी श्रद्धालु संरच्चय और नदी की लहरों के कारण कई बार दुर्घटनाएं घटित होती हैं, जिससे जीवन और संपत्ति को खतरा होता है।

इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्रजघाट में गंगा नदी के घाटों पर फ्लोटिंग बैरिकेट्स और फ्लोटिंग जेट्टी स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह कदम न केवल सुरक्षा के वृच्छिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पर्यावरण और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक सकारात्मक पहल है।

फ्लोटिंग बैरिकेट्स और फ्लोटिंग जेट्टी के लाभ

- सुरक्षा में वृद्धि:** गंगा नदी में श्रद्धालु या अन्य लोग नहाते समय अचानक झूबने की घटनाएं अक्सर होती रही हैं। फ्लोटिंग बैरिकेट्स की स्थापना से इस खतरे को न्यूनतम किया जा सकेगा। ये बैरिकेट्स गहरे पानी को सीमित करेंगे और दुर्घटनाओं के संभावित कारणों को रोकेंगे।
- नावों के लिए पार्किंग व्यवस्था:** गंगा नदी में नावों की नियमित आवाजाही होती है। फ्लोटिंग बैरिकेट्स की मदद से नावों के लिए एक सुरक्षित पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी, जिससे नाविकों को अपनी आजीविका कमाने में आसानी होगी। इसके अलावा, यह नावों के संचालन को सुव्यवस्थित करेगा।
- धार्मिक गतिविधियों का समर्थन:** घाटों पर फ्लोटिंग जेट्टी का निर्माण धार्मिक कार्यों को सुगम बनाएगा। श्रद्धालु पूजा, आरती, विसर्जन आदि आसानी से कर सकेंगे। इससे धार्मिक आयोजनों की प्रक्रिया में कोई विप्रभाव नहीं आएगा और यह स्थान और अधिक आकर्षक बनेगा।
- स्वच्छता बनाए रखना:** गंगा नदी में श्रद्धालुओं द्वारा फूल-माला और अन्य पूजा सामग्री का विसर्जन किया जाता है, जो नदी में प्रदूषण का कारण बन सकता है। फ्लोटिंग बैरिकेट्स के साथ लगाये जाने वाले सेफ्टी नेट्स इन विसर्जन सामग्री को नदी में बहने से रोकेंगे, जिससे नदी की स्वच्छता बनी रहेगी।
- दृश्यात्मक आकर्षण:** गंगा नदी के घाटों पर फ्लोटिंग बैरिकेट्स और जेट्टी का निर्माण इन स्थलों का दृश्यात्मक आकर्षण बढ़ाएगा। पर्यटकों के लिए यह एक नया अनुभव होगा, जो धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय वृच्छिकोण से महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष: ब्रजघाट में फ्लोटिंग बैरिकेट्स और फ्लोटिंग जेट्टी की स्थापना न केवल गंगा नदी के आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी, बल्कि यह पर्यटन, धार्मिक क्रियाओं और स्वच्छता के क्षेत्र में भी एक नया आयाम जोड़ने का काम करेगी। यह कदम न केवल स्थानीय निवासियों के लिए बल्कि पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। इस कार्य के माध्यम से गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त रखने, घाटों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक मजबूत प्रयास किया जा रहा है।

Best Practices

ललितपुर आपदा प्रबंधन एवं जन जागरूकता: उत्तर प्रदेश में बहुआयामी प्रयासों की एक झलक



आपदा प्रबंधन केवल प्राकृतिक आपदाओं से निपटने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समुदाय को सशक्त बनाने का एक माध्यम है, जिससे जीवन और संपत्ति की रक्षा की जा सके। उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिलों में प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, जनप्रतिनिधि और विभाग मिलकर जन-जागरूकता के प्रयासों को गति दे रहे हैं।

1. आशा बहुओं द्वारा बाढ़, लू एवं अतिवृष्टि से संबंधित सुरक्षा उपायों पर जागरूकता अभियान चलाकर ग्रामीणों में आपदा सतर्कता की भावना विकसित की गयी।
2. अग्रिशमन विभाग द्वारा दीपावली पर घर-घर जाकर जन गोचियों का आयोजन कर अग्रिशमन उपकरणों का प्रदर्शन एवं आपातकालीन उपायों की जानकारी दे कर अग्नि सुरक्षा जागरूकता किया गया।
3. NGO के माध्यम से स्कूलों में आपदा जागरूकता को बच्चों के माध्यम से परिवार स्तर तक पहुंचाया गया।
4. कृषक चौपाल एवं जनसंवाद कर आकाशीय बिजली, बाढ़, अनिश्चित मौसम से सुरक्षा उपायों की जानकारी ग्रामीणों को प्रदान की गयी।

निष्कर्ष: जनपद स्तर पर किए जा रहे इन प्रयासों से स्पष्ट है कि आपदा प्रबंधन को केवल एक विभागीय कार्य न मानते हुए इसे सामुदायिक भागीदारी का विषय बनाया गया है। इन अभियानों के माध्यम से समाज के हर वर्ग को जोड़ा जा रहा है, जिससे राज्य में आपदा के प्रति सजग, सक्षम और संवेदनशील समाज का निर्माण संभव हो रहा है।

श्री अक्षय त्रिपाठी (आई०ए०एस०), जिलाधिकारी
श्री अंकुर श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
श्रीमती आरती देवी, आपदा विशेषज्ञ

आपदा प्रबंधन में SDRF और NDRF पुस्तिकाओं का वितरण: एक प्रभावी कदम

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं राहत आयुक्त कार्यालय ने राज्य आपदा मोचक निधि (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि (NDRF) के अंतर्गत सहायता के मानक और मदों की जानकारी देने वाली मुद्रित पुस्तिकाएं तैयार की हैं। इन पुस्तिकाओं का वितरण सीधे जिला आपदा विशेषज्ञों के माध्यम से जनप्रतिनिधियों को किया गया, ताकि वे अपने क्षेत्रों में चरित सहायता पहुंचाने में सक्षम हो सकें।

इस पहल का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों को आपदा सहायता की प्रक्रियाओं और मानकों से भलीभांति अवगत कराना है। यह प्रयास न केवल सहायता प्रक्रिया को पारदर्शी बनाता है, बल्कि जनप्रतिनिधियों और आपदा विशेषज्ञों के बीच समन्वय भी सुहृद करता है। इससे आपदा की स्थिति में प्रभावितों तक शीघ्र और प्रभावी सहायता पहुंचाई जा सकेगी। यह कदम राज्य में आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक सक्षम व भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।



माननीय जन प्रतिनिधिगण को राहत मानक और मदों के पुस्तकों का वितरण

सोनभद्र आकाशवाणी के माध्यम से आपदा जागरूकता का प्रचार-प्रसार

श्री बद्रीनाथ सिंह (आई०ए०एस०), जिलाधिकारी
श्री सहदेव कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
श्री पवन कुमार शुक्ला, आपदा विशेषज्ञ



आकाशवाणी के माध्यम से जनजागरूकता कार्यक्रम

जरूरत है कि रेडियो का माध्यम ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा से संबंधित जानकारी पहुंचाने का एक प्रभावी उपाय है। इस विधि को अपनाकर, अन्य जनपद भी अपने क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ा सकते हैं और लोगों को सही समय पर सही कदम उठाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को कवर किया जा सकता है। इसके तहत, आपदा से पहले, दौरान, और बाढ़ में क्या कदम उठाए जाएं, इस बारे में विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी जा सकती है। इसके अलावा, कॉल-इन शोज के माध्यम से लोगों के सवालों के जवाब भी दिए जा सकते हैं, जिससे लोग और अधिक जागरूक हो सकें।

आकाशवाणी का महत्व

आकाशवाणी, या रेडियो, ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रसार का एक महत्वपूर्ण और सस्ता साधन है। खासकर उन इलाकों में जहाँ इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क की सुविधा नहीं है, रेडियो एक महत्वपूर्ण जरिया बनकर उभरता है। रेडियो पर प्रसारित होने वाली जानकारी न केवल आसानी से लोगों तक पहुंचती है, बल्कि वह उन्हें तत्काल और स्टीक जानकारी भी देती है, जो आपदा के समय आवश्यक होती है।

आपदा जागरूकता का प्रचार-प्रसार

सोनभद्र जिले में आकाशवाणी के माध्यम से विभिन्न आपदाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है। इसमें प्रमुख आपदाएँ जैसे भूकंप, बाढ़, आग, और अन्य प्राकृतिक आपदाएँ शामिल हैं। रेडियो पर प्रसारित होने वाली ये जानकारी न केवल स्थानीय लोगों को आपदा की स्थिति में क्या करना चाहिए, इसके बारे में बताती है, बल्कि यह उन्हें आपदा से बचाव के उपायों और पुनर्प्राप्ति प्रक्रियाओं के बारे में भी जागरूक करती है।

निष्कर्ष: जनपद सोनभद्र द्वारा किया गया यह प्रयास अन्य जनपदों के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है। अन्य जनपदों को भी यह समझने की

Best Practices

मीरजापुर में आकाशीय बिजली से जनहानि रोकने हेतु 80 स्थलों पर लाइटनिंग अरेस्टर की स्थापना

विंध्य क्षेत्र के जनपद मीरजापुर में हर वर्ष आकाशीय बिजली गिरने से बड़ी संख्या में जान-माल की हानि होती है। वर्ष 2023 में इस कारण 27 लोगों की मृत्यु हुई थी। इसे देखते हुए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (SDRF) के अंतर्गत 80 संवेदनशील स्थलों पर लाइटनिंग अरेस्टर स्थापित किए हैं। यह परियोजना जिलाधिकारी महोदया के निर्देशन और अपर जिलाधिकारी (विं/रा०) के मार्गदर्शन में विकसित की गई है।



इसके अंतर्गत:

विगत वर्षों की घटनाओं का डेटा विश्लेषण कर आकाशीय बिजली से प्रभावित स्थानों को चिह्नित किया गया।
इन स्थलों का लाइटनिंग हॉटस्पॉट मैप तैयार किया गया।

श्रीमती प्रियंका निरंजन (आई०ए०एस०), जिलाधिकारी
श्री शिव प्रताप शुक्ला, अपर जिलाधिकारी (विं/रा०)
श्री अंकुर गुप्ता, आपदा विशेषज्ञ

उसके आधार पर चार तहसीलों में लाइटनिंग अरेस्टर लगाए गए:

तहसील सदर:	19 स्थल
तहसील चुनार:	25 स्थल
तहसील लालगंज:	23 स्थल
तहसील मङ्गिहान:	13 स्थल

लाइटनिंग अरेस्टर गिरने वाली बिजली को अवशोषित कर उसे सुरक्षित रूप से भूमि में प्रवाहित कर देते हैं, जिससे लोगों की जान बचाई जा सकती है। इस परियोजना को उत्तर प्रदेश शासन की एप्रेज़ल समिति, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं संबंधित तकनीकी संस्थानों जैसे

IITM-PUNE, CROPC, & IIT Roorkee के विशेषज्ञों द्वारा अनुमोदन और सहयोग प्राप्त हुआ है। स्थानीय स्तर पर अरेस्टरों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी समिति का गठन कर समय-समय पर निरीक्षण भी किया गया।



लाइटनिंग अरेस्टरस जियो टैग लोकेशन

निष्कर्ष: यह परियोजना मीरजापुर जिले में आकाशीय बिजली से होने वाली जनहानि को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और तकनीक आधारित प्रयास है, जो अन्य जिलों के लिए भी अनुकरणीय मॉडल बन सकता है।

गौतमबुद्ध नगर में आपदा प्रबंधन की दृष्टि से बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट पर मोटो जी०पी० 2023 बाइक रेसिंग की तैयारियां

MotoGP Bike Racing Noida

2023 एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की मोटरसाइकिल रेसिंग प्रतियोगिता है, जो दुनिया भर से रेसर्स, तकनीकी टीमें और हजारों दर्शकों को आकर्षित करती है। इस विशाल आयोजन के सफल संचालन और सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट परिसर में किया गया।

इस बैठक में आपदा प्रबंधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण रणनीतियों और व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।

आपदा प्रबंधन की प्रमुख व्यवस्थाएँ:

- * **समन्वय:** आयोजन स्थल पर विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति तथा एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति आपदा की स्थिति में तत्काल और समन्वित प्रतिक्रिया को सुनिश्चित करेगी।
- * **सुरक्षा :** भारी भीड़ को देखते हुए प्रत्येक संवेदनशील क्षेत्र में अधिकारियों की तैनाती की गई है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके और अप्रिय घटनाओं की रोकथाम संभव हो।



माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रेस के दौरान निरक्षण

श्री मनीष कुमार वर्मा (आई०ए०एस०), जिलाधिकारी
श्री अतुल कुमार, अपर जिलाधिकारी (विं/रा०)
श्री ओंकार चतुर्वेदी, आपदा विशेषज्ञ

- * **त्वरित प्रतिक्रिया :** किसी भी आपात स्थिति में, अलग-अलग ड्यूटी पॉइंट्स पर तैनात अधिकारी तत्काल कार्रवाई करते हुए राहत काया में तेजी ला सकेंगे।
- * **संसाधन प्रबंधन :** अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी से आवश्यक संसाधनों का समय पर आवंटन, लॉजिस्टिक समर्थन, और प्राथमिक उपचार जैसी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

निष्कर्ष: यह सक्रिय दृष्टिकोण न केवल मोटो जी०पी० 2023 बाइक रेसिंग के सफल आयोजन के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि किसी भी संभावित आपदा की स्थिति में जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है। जिला प्रशासन का यह कदम एक जिम्मेदार और आपदा प्रबंधन के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण को दर्शाता है।



रेस ट्रैक लेआउट

Case Study

जनसठ, मुज़फ्फरनगर (यूपी) में दो मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का ढहना राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, 8 वीं वाहिनी गाज़ियाबाद

14 अप्रैल 2024 को 1700 बजे एक दो मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जनसठ, मुज़फ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में ढह गया। यह ढहना सड़क के चार लेन के निर्माण के कारण हुआ, जिससे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की नींव उठ गई और पूरी इमारत पैनकेक की तरह ढह गई, जिसके परिणामस्वरूप 19 लोग मलबे में फंस गए।

घटना स्थान:

- * निर्देशांक: 29°19'40.9" N, 77°51'42.3" E
- * जनसठ, मुज़फ्फरनगर, दिल्ली से 118 किमी दूर स्थित है। यह क्षेत्र समतल है और यहाँ हल्की और रेतीली मिट्टी पाई जाती है।

संवेदनशीलता प्रोफाइल:

- * यह क्षेत्र भूकंप क्षेत्र IV में आता है, जिसका मतलब है कि यह भूकंप के प्रति अधिक संवेदनशील है, हालांकि इससे पहले ऐसी कोई घटना नहीं हुई है।

NDRF की त्वरित प्रतिक्रिया:

- * समय: घटना की सूचना जिले प्रशासन से 1815 बजे प्राप्त हुई। टीमों की तैनाती:
 - * Alert-I Vhe (8G) 1815 बजे रवाना हुई।
 - * Alert-II Vhe (8Q) 1830 बजे रवाना हुई।
 - * कुल बल: 4 GOs, 8 SOS, 62 ORS
 - * उपकरण: CSSR SOP के तहत उपकरण, हल्के वाहन, VHF संचार।
 - * कमांड और नियंत्रण: संचालन की निगरानी 8वीं बटालियन NDRF के कमांडेंट द्वारा की गई।

योजना और संचालन की निष्पत्ति:

- * प्रारंभिक आकलन:
 - * 20:26 बजे NDRF टीम घटना स्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों और घटना कमांडर से जानकारी प्राप्त की। 18 लोग पहले ही बाहर निकाले जा चुके थे और 1 व्यक्ति मलबे में फंसा हुआ था।
 - * ढहने की स्थिति ऐसी थी कि क्षैतिज तरीके से पहुंच पाना मुश्किल था, इसलिए ऊर्ध्वाधर ब्रिंचिंग और तकनीकी टीम की आवश्यकता थी।
- * खोज और बचाव:
 - * भौतिक खोज: शुरू में भौतिक खोज की गई, लेकिन पीड़ित का पता नहीं चल सका।
 - * K9 खोज: कुत्तों से खोज करने के बाद भी कोई जानकारी नहीं मिली।
 - * रेस्क्यू टीम: टीम ने VLC (वर्टिकल लिफ्ट क्रेन) का उपयोग करके और स्लैब को तोड़कर पीड़ित को ढूँढ़ा।
 - * पीड़ित की पहचान: पीड़ित को 30 फीट नीचे ढह चुके स्लैब के नीचे पाया गया।
- * बचाव का कार्य:
 - * ब्रिंचिंग और शोरिंग: टीम ने स्लैब को तोड़ने और उसे स्थिर करने के लिए शोरिंग की।
 - * चिकित्सीय सहायता: NDRF के चिकित्सा अधिकारी ने पीड़ित को IV फ्लूइड दिया और दर्द निवारक दवाएं दीं। बचाव प्रक्रिया अत्यंत सावधानी से की गई, क्योंकि पीड़ित की स्थिति गंभीर थी और मलबा अस्थिर था।

* अंतिम निकासी:

- * पीड़ित बिकेश (30 वर्ष) स्लैब के नीचे फंसा हुआ था, और उसके पेट में स्टील की छड़ घुसी हुई थी।
- * मिनी ग्राइंडर का उपयोग करके स्टील की छड़ को काटा गया, जबकि बचावकर्ता और चिकित्सा अधिकारी शारीरिक रूप से पीड़ित को सहारा दे रहे थे।
- * 0400 बजे पीड़ित को सुरक्षित रूप से मलबे से बाहर निकाला गया और उसे ALS एंबुलेंस द्वारा अस्पताल भेजा गया।

* इस अॉपरेशन में विभिन्न एजेंसियों का सहयोग प्राप्त हुआ:

- * राज्य पुलिस: घटना स्थल पर कानून-व्यवस्था बनाए रखा।
- * UP फायर सर्विस: आग बुझाने और मलबे को हटाने में सहायता की।
- * UP SDRF: बचाव कार्य में समर्थन।
- * स्वास्थ्य विभाग: चिकित्सा सहायता प्रदान की।
- * स्वयंसेवक: स्थल प्रबंधन और लॉजिस्टिक्स में मदद की।

* चुनौतियाँ

- * भीड़ नियंत्रण: पुलिस की उपस्थिति के बावजूद भीड़ घटना स्थल पर बार-बार लौट रही थी, जिससे बचाव कार्य में रुकावट आ रही थी।
- * मलबा हटाने की प्रक्रिया: ढहे हुए क्षेत्र में भारी मलबा था, जिसे हटाने में समय लगा।

* प्रमुख उपलब्धियाँ और नवाचार

- * जीवित बचाव: एक जीवित व्यक्ति का सफलतापूर्वक बचाव किया गया।
- * नवाचार: बचावकर्ताओं द्वारा शारीरिक रूप से सहारा देना और स्टील की छड़ को काटने के दौरान यह एक नई और चुनौतीपूर्ण पहल थी, जिससे पीड़ित को बचाया जा सका।

* सीखे गए पाठ

- * शोरिंग का महत्व: अस्थिर संरचनाओं को स्थिर करना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि बचावकर्ता और पीड़ित दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
- * चिकित्सीय सहायता: बचाव के दौरान तुरंत चिकित्सा हस्तक्षेप पीड़ित की स्थिति को स्थिर करने के लिए आवश्यक है।

* भविष्य के प्रशिक्षण के लिए सुझाव

- * बड़े ढहने वाले स्थल से निपटने पर प्रशिक्षण: NDRF के भविष्य के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बड़े और जटिल ढहने की स्थितियों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।
- * भीड़ प्रबंधन रणनीतियाँ: उच्च यातायात वाले बचाव कार्यों में प्रभावी भीड़ नियंत्रण रणनीतियों को शामिल किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष: यह केस स्टडी यह दर्शाती है कि संरचनात्मक ढहने के घटनाओं में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया आवश्यक होती है। NDRF की त्वरित तैनाती, तकनीकी विशेषज्ञता और समन्वित दृष्टिकोण ने एक जीवित व्यक्ति को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अॉपरेशन ने धैर्य, शोरिंग तकनीकों और चिकित्सा तत्परता की महत्ता को रेखांकित किया।

आपदा समाचार

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (UP SDMA)



Uttar Pradesh State Disaster Management Authority (UP SDMA)

Address: B-1 Block, PICUP Bhawan, PICUP Building Road, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh, 226010

upsdma@gmail.com 0522-2306882

For more information, visit our web at www.upsdma.up.nic.in